बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

दिनांक–10.09.2015 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कमजोर रहने के फलस्वरूप सामान्य से कम वर्षा के आलोक में सम्पन्न आपदा प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक की कार्यवाही:–

उपस्थिति :–

1. विकास आयुक्त
2. प्रधान सचिव, कृषि विभाग
3. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग
4. प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग
5. प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
6. सचिव, जल संसाधन एवं लघु जल संसाधन विभाग
7. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
8. सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
9. सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
10. वरीय संयुक्त निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
11. मुख्य अभियंता (O&M) , NBPDCL, for बिहार स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड

दक्षिण–पश्चिम मानसून 2015 से राज्य में अल्प वर्षापात/सुखाड़ की संभावना को देखते हुए आपातकालीन प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक में विभागवार समीक्षा की गई और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया जो निम्नवत है :–

1. भारत मौसम विज्ञान विभाग

भारत मौसम विज्ञान विभाग के प्रतिवेदन के अनुसार वर्त्तमान में राज्य में वर्षापात सामान्य से 24 प्रतिशत कम है, जिसमें सात जिले यथा भोजपुर, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्णियाँ, सहरसा एवं सीतामढ़ी का वर्षापात सामान्य से 40 प्रतिशत कम है।

मुख्य सचिव द्वारा इन सातो जिलों के अतिरिक्त अररिया जिला पर भी विशेष निगरानी रखने का निदेश दिया गया।

2. कृषि विभाग

प्रधान सचिव, कृषि विभाग द्वारा बताया गया कि अबतक धान की बिचड़े का आच्छादन लक्ष्य के विरूद्ध 95.33 प्रतिशत, धान का आच्छादन 97.87 प्रतिशत एवं मक्का का आच्छादन 89.69 प्रतिशत हुआ है। उनके द्वारा बताया गया कि मानसून की कमजोर स्थिति के मद्देनजर

धान के उत्पादन के साथ–साथ बड़े क्षेत्रफल में मक्का के उत्पादन पर भी बल दिया जा रहा है। खरीफ 2015 में सामान्य से कम वर्षापात के पूर्वानुमान के आलोक में राज्य में 350000 हेक्टेयर क्षेत्र में आकस्मिक फसल योजना के अन्तर्गत विभिन्न फसलों के आच्छादन का कार्यक्रम है। डीजल सब्सिडी के रूप में 10.79 करोड़ का वितरण किया गया है।

मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि पूर्णियाँ, सहरसा, सीतामढ़ी, मधुबनी, भोजपुर, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर एवं अररिया इन आठ जिलों में डीजल अनुदान निकासी एवं वितरण में काफी अंतर है इसकी जांच की जाए। साथ ही इन आठ जिलों के प्रभारी सचिव को भ्रमण कर सुखाड़ की स्थिति का आकलन कर प्रतिवेदन देने का निदेश दिया गया। अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त कर इसका सत्यापनोपरांत डीजल अनुदान वितरण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ के द्वारा डीजल अनुदान की राशि वितरण नहीं किये जाने के आलोक में प्रधान सचिव, कृषि विभाग को स्पष्टीकरण पुछने का निदेश दिया गया।

3. लघु जल संसाधन विभाग

लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा यांत्रिक एवं विद्युत दोष से बंद पड़े नलकूपों के स्थिति का प्रतिवेदन समर्पित किया गया है जिसके अनुसार विद्युत दोष के कारण 689 नलकूप बंद हैं एवं यांत्रिक दोष से बंद पड़े नलकूपों की सं0 1173 तथा संयुक्त दोष से बंद पड़े नलकूपों की सं0 3935 है।

मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि नलकूपों की मरम्मति एवं Channels की मरम्मति अविलम्ब पूरी की जाय और साथ ही शीघ्र नलकूपों को चलाने हेतु कर्मियों की व्यवस्था की जाए एवं नलकूपों से सिंचित होने वाले क्षेत्रफल का प्रतिवेदन की मांग की गयी।

4. ऊर्जा विभाग

ऊर्जा विभाग के प्रतिवेदन के अनुसार राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु पर्याप्त विद्युत की आपूर्त्ति की जा रही है, जो औसत 17.55 घंटे है। 174 जले ट्रांस्फर्मर के विरूद्ध 143 ट्रांस्फर्मर बदले जा चूके हैं तथा नाबार्ड फेज–XI के 2697 स्कीम के विरूद्ध 2443 को ऊर्जान्वित कर दिया गया है। इसी प्रकार नाबार्ड फेज–VIII के अंतर्गत 1551 स्कीम के विरूद्ध 1243 को ऊर्जान्वित कर दिया गया है।

मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि अल्पवर्षापात की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति जारी रखी जाए तथा ट्रांस्फर्मर की खराबी से बंद पड़े नलकूपों को शीघ्र ऊर्जान्वित करने की कार्रवाई की जाए।

5. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा बताया गया कि कुल 9699 चापाकल गाड़ने के लक्ष्य के विरूद्ध 18053 चापाकल गाड़ा जा चूका है तथा कुल 9695 चापाकल मरम्मति लक्ष्य के विरूद्ध 61361 चापाकल की मरम्मति की जा चूकी है। विभाग द्वारा हर जिला के प्रत्येक प्रखण्ड के 5 चापाकलों के भू–जलस्तर की मोनेटरिंग की जा रही है। राज्य के दक्षिण भाग के 17 जिलों में माह अगस्त 2013 की तुलना में किसी भी जिला में औसतन भू–जल स्तर में गिरावट की सूचना नहीं है। माह अगस्त 2014 की तुलना में राज्य के

दक्षिणी भाग के भी किसी भी जिले में औसत भू–जलस्तर की गिरावट नहीं पायी गई है। राज्य के उत्तरी भाग के 21 जिलों में अगस्त 2014 की तुलना में किसी भी जिले में भू–जलस्तर में गिरावट की सूचना नहीं है।

मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि विद्युतदोष के कारण खराब नलकूपों की सूची ऊर्जा विभाग को उपलब्ध कराया जाए। यह भी ध्यान दिया जाय कि गुणवतापूर्ण पेयजल की आपूर्ति किया जाय और जहां बोरिंग पुराना हो गया है उसे मरम्मति करने की अविलम्ब कार्रवाई की जाय।

6. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि पशु शिविरों के स्थापना हेतु 1640 स्थालों का चयन कर लिया गया है एवं पशुचारे की कोई कमी नहीं है। 10 प्रकार पशु दवाओं का क्रय किया जा चूका है एवं टीकाकरण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि पशु शिविरों हेतु चयनित स्थलों के पास पशुओं के पेयजल हेतु जल के स्रोत उपलब्ध है अथवा नहीं इसकी जाँच करा ली जाए।

7. जल संसाधन विभाग

सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि कोशी नदी में कुल 102185 घनसेक जलश्राव प्रवाहित हो रहा है। पूर्वी कोशी एवं पश्चिम कोशी नहर प्रणालियों में क्रमशः 12000 तथा 1000 घनसेक जलश्राव दिया जा रहा है। गंडक नदी में वर्त्तमान में कुल 61500 घनसेक जलश्राव प्रवाहित हो रहा है, जिसमें से तिरहुत नहर प्रणाली में 4000 घनसेक, दोन नहर प्रणाली में 1500 घनसेक एवं त्रिवेणी नहर प्रणाली में 500 घनसेक जलश्राव दिया जा रहा है। पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली में 9050 घनसेक जलापूर्ति की जा रही है जिसमें से सारण मुख्य नहर प्रणाली में 2400 घनसेक जलश्राव दिया जा रहा है। सोन नदी के इन्द्रपुरी बराज में 13760 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है जिसमें से पूर्व नहर प्रणाली में 4490 घनसेक तथा पश्चिमी नहर प्रणाली में 9610 घनसेक जलश्राव दिया जा रहा है। उनके द्वारा बताया गया कि जलाशयों में जल भंडारण की पूर्व की स्थिति से सुधार है।

प्रमुख जलाशयों में जल भंडारण की स्थिति निम्नवत है:–

क्र0	जलाशय का नाम	कुल संचयन क्षमता	दिनांक–04.09.2015 की स्थिति (फीट में)	दिनांक–10.09.2015 की स्थिति (फीट में)
1	चन्दन	110000	496.80	497.00
2	बदुआ	89000	418.30	413.80
3	ओढ़नी	33550	405.60	404.30
4	ऑजन	20030	403.00	386.00
5	बेलहरना	11805	452.50	441.70
6	खड़गपुर झील	13200	222.20	215.70
7	विलासी	23400	295.00	289.00
8	मोरवे	10800	271.60	257.40

9	नागी	7700	431.80	432.50
10	गरही जलाशय	68500	546.60	542.80
11	कोहिरा	22210	316.80	328.80
12	बटाने	48600	732.00	738.25
13	फुलवरिया	41563	586.00	577.00
14	नकटी जलाशय	11320	446.00	443.10

खरीफ सिंचाई 2015 के दौरान नहरों से किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की स्थिति

क्र0	नहर प्रणाली का नाम	सिंचाई लक्ष्य (हे0 में)	सिंचाई उपलब्धि (हे0 में) दिनांक–04.09.15 तक	सिंचाई उपलब्धि (हे0 में) दिनांक–10.09.15 तक
(क)	सोन नहर प्रणाली :–			
1.	पूर्वी सोन नहर प्रणाली	148450	145834	145834
2.	पश्चिमी सोन नहर प्रणाली	399922	360203	360203
(ख)	कोशी नहर प्रणाली :–			
1.	पूर्वी कोशी नहर प्रणाली	3 7565	296832	314167
2.	पश्चिमी कोशी नहर प्रणाली	41384	26015	32039
(ग)	गंडक नहर प्रणाली :–			
1.	पूर्वी गंडक नहर प्रणाली	331684	302368	302368
2.	पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली	165846	151320	151320
(घ)	अन्य योजनाएं :–	453490	340782	365632
कुल		**1918341**	**1623354**	**1671613**

सचिव, जल संसाधन विभाग के द्वारा बताया गया कि सोन नदी में पानी कम है एवं जिसके लिए वाणसागर जलाशय से 5 हजार घनसेक जलश्राव की मांग की गई थी। वाणसागर जलाशय से पानी छोड़ दिया गया है जो रविवार तक सोन नहर में पहुंच जायेगा तथा जलस्राव पूर्व की भांति 14000 धनसेक हो जायेगा। वर्त्तमान में राज्य के सभी तटबंध सुरक्षित है तथा बाढ़ से तटबंधों को बचाने हेतु सतत निगरानी रखी जा रही है।

मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि नहरों की सभी वितरणी को ठीक करा लें और बांधों की मरम्मति भी सुनिश्चित कर लें। सभी गेट सही है कि नहीं यह भी देख लें तथा नहरों से अन्तिम छोर तक सिंचाई हेतु पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि जलाशयो के जल भंडारण की स्थिति की जांच मुख्यालय से टीम भेजकर करा ली जाए।

8. ग्रामीण विकास विभाग

सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बताया गया कि मनरेगा अंतर्गत 1.25 करोड़ पेन्डेंज सृजित हो गया है।

मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि मनरेगा के अंतर्गत विभिन्न जिलों में कितने पेड़ लगे हैं, इसका प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया तथा जिन क्षेत्रों में वर्षापात कम है उन क्षेत्रों की स्थिति पर सतत् निगरानी रखी जाए तथा मैनडेज बढ़ाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए। उनके द्वारा इस वर्ष सृजित मैनडेज का तुलना पिछले वर्ष में सृजित मैनडेज से करने का निदेश सचिव, ग्रामीण विकास विभाग को दिया गया।

9. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा बताया गया कि राज्य में खाद्यान्न की कमी नहीं है एवं खाद्यान्न भंडारित है।

मुख्य सचिव द्वारा शताब्दी अन्न कलश योजना अंतर्गत प्रत्येक पंचायतों/ वार्डो में खाद्यान्न की स्थिति/उपलब्धतता के संबंध में ज्ञात करने का निदेश दिया गया।

10. स्वास्थ्य विभाग

प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया कि स्वास्थ्य केन्द्रो में पर्याप्त मात्रा में मानव दवा के भंडारण की कार्रवाई की जा रही है। मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सूखे की स्थिति उत्पन्न होने की स्थिति के लिए अग्रिम कार्य योजना तैयार कर ली जाय।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी। अगली बैठक दिनांक 18.09.2015 को 5.30 बजे अपराह्न आहूत करने का निर्णय लिया गया।

ह0/–
(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव
बिहार

ज्ञापांक 1प्रा0आ0–07/2014...../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः कृषि उत्पादन आयुक्त/ प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग/पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/जल संसाधन विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ कृषि विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ उर्जा विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/ निदेशक, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग/ निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(अनिरूद्ध कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक 1प्रा0आ0–07/2014.3567...../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 14/9/15

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/ विकास आयुक्त बिहार के प्रधान आप्त सचिव/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

14/9/15
विशेष सचिव